

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग  
केंद्रीय जल आयोग  
जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय



Government of India  
Ministry of Jal Shakti  
Dept. of Water Resources, RD&GR  
Central Water Commission  
Water System Engineering Directorate

दिनांक: 05.02.2020

**विषय - समाचार पत्रों की कटिंग का प्रस्तुतिकरण।**

जल संसाधन विकास और संबद्ध विषयों से संबंधित समाचार पत्रों की कटिंग को केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष के अवलोकन के लिए संलग्न किया गया है। इन समाचारों की कटिंग की सॉफ्ट कॉपी केन्द्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी।

संलग्नक: उपरोक्त

अंश  
05.02.2020

वरिष्ठ कलाकार  
जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय

उप निदेशक, (ज. प्र. आ.) निदे०

विचि  
05/02/2020

निदेशक, (ज. प्र. आ.) निदे०

प्रमुख निदेशक  
05-02-2020

सेवा में,

अध्यक्ष, के. ज. आ., नई दिल्ली

जानकारी हेतु - सभी संबंधित केन्द्रीय जल आयोग की वेबसाइट [www.cwc.gov.in](http://www.cwc.gov.in) पर देखें।



Hindustan Times (New Delhi)  
The Statesman (New Delhi)  
The Times of India (New Delhi)  
The Indian Express (New Delhi)  
The Hindu (Delhi)  
Pioneer (Delhi)  
राष्ट्रीय सहारा (दिल्ली)

☐ Deccan Herald (Bengaluru )  
☐ Deccan Chronicle  
☐ The Economic Times (New Delhi)  
☐ Business Standard (New Delhi)  
☐ The Tribune (Gurugram)  
☐ Financial Express  
☐ दैनिक भास्कर (नई दिल्ली)

☐ हिंदुस्तान (नई दिल्ली)  
☐ नव भारत टाइम्स (नई दिल्ली)  
☐ पंजाब केसरी (दिल्ली)  
☐ राजस्थान पत्रिका (नई दिल्ली)  
☐ दैनिक जागरण (नई दिल्ली)  
☐ जनसत्ता (दिल्ली)  
☐ अमर उजाला (नई दिल्ली)

☐  
☐  
☐  
☐  
☐  
☐  
☐

and documented at WSE Dte, CWC.

**Assam Tribune, Guwahati** ✓

## Volunteers clean Maklang river in Imphal West dist



*Volunteers cleaning the Maklang river at Khumbong village in Manipur on Sunday.  
– Photo: Correspondent*

### **SOBHAPATI SAMOM**

**KHUMBONG, Feb 4:** With the motto 'Save River, Save Water', the residents of Khumbong area in Imphal West district conducted a two-day river cleaning camp along the Maklang river on February 1 and 2.

The camp, which covers the Khumbong sector of the river measuring more than one kilometre, was organised under the aegis of the Imphal West Students' Club (IWSC) and the Developing Farmers' Association (DFA).

"The idea of holding the cleaning camp is to save the Maklang river from pollution," said IWSC secretary

A Samarendra. "The river plays an important role in meeting our daily water requirements as no piped water is available in our locality," he added.

The nearly 3,000 population of Khumbong village, located about 15 km west of the Manipur capital, depends on the Maklang river, which originates from the hill ranges behind the Sangaitheh area, for daily use and irrigation purposes as well. The small river also plays a vital role for other villages like Maklang, Ngairangbam, Khumbong, Khaidem, Heigrujam and Nambol before flowing down to the Loktak Lake.

During the river cleaning

camp held for the first time, around 50 volunteers collected plastic waste and other forms of garbage generated from the Khumbong market, the DFA president said. The efforts of the volunteers have been appreciated by the elders of Khumbong.

Earlier, people residing under 12 Imphal municipal wards located between Irishemba and Heirangoithong areas in Imphal West district, participated in a cleanliness drive of the Nambul river, considered one of the most polluted rivers of the State. The drive was initiated by the Directorate of Environment, along with other line departments, last year.

Hindustan Times (New Delhi)  
The Statesman (New Delhi)  
The Times of India (New Delhi)  
The Indian Express (New Delhi)  
The Hindu (Delhi)  
Pioneer (Delhi)  
राष्ट्रीय सहारा (दिल्ली)

☐ Deccan Herald (Bengaluru )  
☐ Deccan Chronicle  
☐ The Economic Times (New Delhi)  
☐ Business Standard (New Delhi)  
☐ The Tribune (Gurugram)  
☐ Financial Express  
☐ दैनिक भास्कर (नई दिल्ली)

☒ हिंदुस्तान (नई दिल्ली)  
☐ नव भारत टाइम्स (नई दिल्ली)  
☐ पंजाब केसरी (दिल्ली)  
☐ राजस्थान पत्रिका (नई दिल्ली)  
☐ दैनिक जागरण (नई दिल्ली)  
☐ जनसत्ता (दिल्ली)  
☐ अमर उजाला (नई दिल्ली)

and documented at WSE Dte, CWC.

## REVIVAL CARNIVAL

# A festival on the banks of Hemavathi for 'clean rivers'

**RASHEED KAPPAN**  
BENGALURU, DHNS

**R**iver festivals are a new concept in eco-tourism. One of Karnataka's first such festivals is just around the corner in Sakleshpur, (Hassan district) barely 200 km from Bengaluru. The two-day 'NADi' festival is all set to come alive on the banks of Hemavathi river on February 15 and 16.

In the news for all the wrong reasons – pollution, encroachment, sand-mining -, the state's rivers are not exactly on a high. The festival organisers say they want to change this perception, dubbing the festival as a campaign for "clean rivers."

Mixing nature, adventure and discovery, NADi would also be about promoting zero-waste and no-single-use plastic.

Lined up for the two-day event on the river bank with the Karle homestay as base are water-based competitions, land-based contests, camping by the river, music



**Rope bridge crossing is organised as part of several activities lined up for the NADi river festival in Sakleshpur.**

and folk art performances, workshops, a flea market and caravan tourism.

Here's more on the water competitions: Boating, kayaking and paddle-boat races, raft-building with waste material and rope activities right on the river. The land-based contests are all about treasure hunts, slow-cycle races and rural games.

Nature photography, fishing, pottery and dance are part of the workshops lined

up for the festival. Supported by the state department of Tourism, Hassan, the event should promote Karnataka tourism while ensuring that natural ecosystems are not impacted, as Hassan Deputy Commissioner R Girish put it.

Curated to resonate the "clean rivers" theme, the Nature, Adventure, Discovery and I (NADi) festival would eventually morph into an annual event. To sync with that thematic

essence, the raft-building activity this time would be done exclusively from plastic waste, the organisers informed.

While V Ramprasad from the Friends of Lakes, Bengaluru will be there to ensure that the event is a zero-waste festival, a cross-country run in Karle has been designed to highlight the river Hemavathi's importance.

This is critical, as recent Central Pollution Control Board data shows that nearly 63% of the urban untreated sewage currently flows into rivers (over 62 billion litres a day), adversely impacting lives and environment.

The festival organisers put the eco theme in perspective: "Unbridled and irresponsible tourism is adding to mess with tourists throwing plastic water bottles, wrappers and other waste without batting an eyelid. There is not only need to run sustained eco-tourism campaigns but events which reflect what we stand for."

# फॉस्फोरस वाली झीलों में जनमा था जीवन

NBT-5/2.

इन झीलों के वाष्पीकरण की दर अधिक होती है जिसकी वजह से इनमें क्षार और लवण की मात्रा ज्यादा होती है। ये सभी सातों महाद्वीप में पाई जाती हैं



मुकुल व्यास

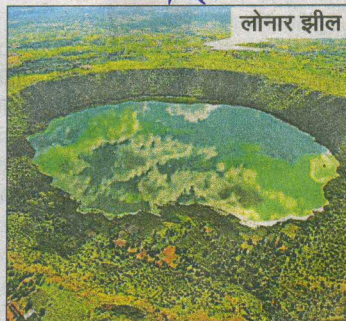
पृथ्वी पर जीवन के प्रारंभिक संकेत उन झीलों में उत्पन्न हुए थे जहां फॉस्फोरस की अधिक मात्रा थी और इस रसायन की अधिकता इन झीलों में मौजूद कार्बन की वजह से थी।

यह नतीजा वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों ने अपनी हालिया स्टडी में निकाला है। इसके लिए इन वैज्ञानिकों ने कैलिफोर्निया की मोनो लेक और भारत की लोनार झील समेत उन तमाम झीलों से नमूने एकत्र किए, जहां कार्बन की मात्रा अधिक थी।

जीवन के लिए फॉस्फोरस आवश्यक है। यह जीवन के छह अनिवार्य रसायनों में एक है। यह डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूलस की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन यह तत्व बहुत मुश्किल से मिलता है। इसी वजह से वैज्ञानिक पिछले पचास वर्षों से इस बात को लेकर माथापच्ची कर रहे हैं कि पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न करने के लिए समुचित फॉस्फोरस कहाँ

से आया? नए अध्ययन में दावा किया गया है कि कार्बन बहुल झीलों में फॉस्फोरस के उच्च स्तर ने फॉस्फेट के मॉलिक्यूलस को दूसरे रसायनों के साथ बिना जुड़े रहने दिया। इस स्थिति में हुई रासायनिक क्रियाओं में डीएनए और आरएनए के शुरुआती गुच्छे पैदा हुए। अपने अध्ययन के लिए रिसर्चरों ने उन झीलों पर ध्यान केंद्रित किया जो शुष्क माहौल में निर्मित होती हैं। इन झीलों की वाष्पीकरण दर अधिक होती है जिसकी वजह से उनमें क्षार और लवण की मात्रा ज्यादा होती है। इन झीलों को क्षारीय और लवणीय झीलों भी कहा जाता है और ये सभी सातों महाद्वीप में पाई जाती हैं। रिसर्चरों ने खास तौर पर कैलिफोर्निया की लेक मोनो, केन्या की मगाडी झील और भारत की लोनार झील में फॉस्फोरस की मात्रा पर गौर किया। उनका कहना है कि इन झीलों में फॉस्फोरस के उच्च स्तर से पता चलता है कि इनमें किसी कुदरती कारण से यह खनिज अधिक मात्रा में जमा होता गया। रिसर्चरों ने पाया कि कार्बन बहुल झीलों में फॉस्फोरस का स्तर समुद्री पानी से 50,000 गुणा अधिक है।

आज ये झीलें जैविक दृष्टि से सक्रिय हैं और इनमें विविध जीव-जंतुओं का वास है। जीव-जंतुओं की मौजूदगी से झील की केमिस्ट्री पर असर पड़ता है। इसलिए शुरुआती झील के पानी की सही समझ बनाने



लोनार झील

## ज्ञान-विज्ञान

के लिए रिसर्चरों ने प्रयोगशाला में अलग से कार्बन बहुल झीलों के पानी की जांच की। उन्होंने विभिन्न रासायनिक संरचनाओं को लेकर झील के पानी के परीक्षण किए ताकि यह पता लगाया जा सके कि झीलों किस प्रकार फॉस्फोरस को जमा करती हैं और एक निर्जीव वातावरण में फॉस्फोरस किस प्रकार उच्च स्तर पर पहुंच जाता है?

अध्ययन के सह-लेखक और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में पृथ्वी विज्ञान के प्रोफेसर डेविड कैटलिंग का कहना है कि झीलों में फॉस्फेट के उच्च स्तर ने ऐसी रासायनिक क्रियाओं को संचालित किया होगा जिनसे फॉस्फोरस आरएनए, प्रोटीन और फैट के निर्माणाधीन

मॉलिक्यूलस में पहुंचा। हम जानते हैं कि ये सारे मॉलिक्यूलस जीवन को चलाने के लिए आवश्यक हैं। करीब चार अरब वर्ष पहले पृथ्वी के प्रारंभिक दिनों में हवा में कार्बन डाई ऑक्साइड की बहुलता ने झीलों के निर्माण और उन्हें फॉस्फोरस के अधिकतम स्तर तक ले जाने में मदद की होगी। इसके अलावा कार्बन डाई ऑक्साइड पानी में घुल कर ऐसी अम्लीय परिस्थितियां उत्पन्न करती है जो चट्टानों से फॉस्फोरस को मुक्त करने में सहायक होती है।

शुरुआती पृथ्वी पर ज्वालामुखियों की सक्रियता अधिक थी। अतः कार्बन डाई ऑक्साइड से क्रिया करने के लिए पर्याप्त ज्वालामुखीय चट्टानें उपलब्ध थीं। इन्होंने झीलों को समुचित मात्रा में कार्बोनेट और फॉस्फोरस की आपूर्ति की होगी। प्रारंभिक पृथ्वी पर अवश्य ही कार्बन से संपन्न झीलों की अधिकता रही होगी जिनमें फॉस्फोरस के उच्च स्तर ने जीवन की निर्माण प्रक्रिया आरंभ की। प्रसंगवश, इसी अध्ययन के लेखकों ने हाल में किए गए एक दूसरे अध्ययन में कहा था कि कार्बन बहुल झीलों समुचित मात्रा में साइनाइड भी उपलब्ध करा सकती हैं। यह रसायन एमिनो एसिड्स और न्यूक्लियोटॉयड के निर्माण में मदद करता है जो प्रोटीन, डीएनए और आरएनए की निर्माण इकाइयां हैं।

RAJASTHAN PATRIKA - 05.02.2020

प्रसंगवश

RP-5/2

## कब तय होगी जवाबदेही

सिं चाई परियोजना किसी भी क्षेत्र की समृद्ध कृषि का द्योतक होती है और नहरें उस क्षेत्र की जीवन रेखाएं। लेकिन कुप्रबंधन के चलते कई बार यही जीवन रेखाएं भूमिपुत्रों को खून के आंसू रुला देती हैं। वागड़ में कुछ वर्षों से यही हो रहा है। जल संसाधन विभाग की लापरवाही और प्रशासनिक अधिकारियों की अरुचि के चलते नहरें किसानों के लिए अभिशाप-सी बनी हुई हैं। माही बजाज सागर परियोजना, सोम कमला आंबा बांध, लोडिसर, अमरपुरा, मारगिया, सब जगह एक से हालात हैं। हर साल जलप्रवाह से पूर्व जल वितरण समितियों की बैठकों में बांध और नहरों की स्थिति, मरम्मत और सफाई प्रबंधन आदि पर चर्चा कर सर्वसम्मति से जलप्रवाह की तिथियां तय करनी होती हैं, लेकिन अधिकारी मनमानी करने से गुरेज नहीं करते।

किसान इन बैठकों में जर्जर व मलबे से अटी नहरों की समस्या को चिल्ला-चिल्ला कर बयां करते हैं, पर इन पर ध्यान नहीं दिया जाता। पाबंद किए जाने के बावजूद जल संसाधन विभाग के अधिकारी किसानों से फीडबैक नहीं लेते। फिर जलप्रवाह के साथ सीपेज और ओवरफ्लो शुरू हो जाता है। नहर के अग्रछोर में खेत के खेत जलमग्न हो जाते हैं और मेहनत पर पानी फिर जाता है। वहीं, अंतिम छोर के काश्तकार पूरे सीजन पानी की एक बूंद का इंतजार करते रहते हैं। माही परियोजना और सोम कमला आंबा बांध नहरों की दशा सुधारने के लिए पिछले कुछ सालों में सरकार ने करोड़ों रुपए स्वीकृत किए, लेकिन जमीनी हकीकत सबके सामने है। समस्या बजट की नहीं, बल्कि इच्छाशक्ति और किसानों की पीड़ा के प्रति संवेदनशीलता की कमी की है। जल वितरण समितियों की बैठकों को औपचारिक होने से रोकना होगा, नहरों में जलप्रवाह के साथ हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए जवाबदेही तय करनी होगी और सफाई के लिए मनरेगा के मस्टररोल जारी कर इतिश्री करने की प्रवृत्ति बंद कर काम की पूरी मॉनिटरिंग करनी होगी। तभी भूमि पुत्रों को सिंचाई सुविधा का पूरा लाभ मिल सकेगा।

## कुओं से बुझ सकती है प्यास

**बु**

देलखंड की प्यास, पलायन, अल्प वर्षा अब किसी की संवेदना को जागृत नहीं करती। सभी मान बैठे हैं कि यह इस इलाके की नियति है। होली बीतते-बीतते

गांव के गांव खाली हो जाएंगे। कई हजार करोड़ का बुंदेलखंड विशेष पैकेज यहां के कंठ तर नहीं कर पाया। एक दशक के दौरान तीन बार उम्मीद से कम मेष बरसना बुंदेलखंड की सदियों की परंपरा रही है। यहां के पारंपरिक कुएं, तालाब और पहाड़ कभी समाज को इंद्र की बेरुखी के सामन झुकने नहीं देते थे। समझना होगा कि इस क्षेत्र की प्यास का हल किन्हीं बड़ी परियोजनाओं में नहीं है, इसका स्थायी समाधान पारंपरिक जल स्रोतों को स्थानीय स्तर पर संभालने में ही है। खासकर मजरे-गांव-मुहल्लों की प्यास की कुंजी उन कुओं के पास ही है, जिन्हें समाज नल से घर तक पानी आने की आस में नष्ट कर चुका है।

बुंदेलखंड की असली समस्या अल्प वर्षा नहीं है, वह तो यहां सदियों, पीढ़ियों से होती आई है। बड़े करीने से यहां के आदि-समाज ने बूंदों को बचाना सीखा था। दो तरह के तालाब- एक केवल पीने के लिए, दूसरे केवल मवेशी और सिंचाई के लिए होते थे। पहाड़ की गोदी में बस्ती और पहाड़ की तलहटी में तालाब। तालाब के इर्द-गिर्द कुएं, ताकि समाज को जितनी जरूरत हो, उतना पानी खींच कर इस्तेमाल कर ले। छठे दशक तक इस अंचल में 60 हजार से ज्यादा कुएं और कोई 25 हजार छोटे-बड़े तालाब हुआ करते थे। बुंदेलखंड की पुश्तौं पुरानी परंपरा रही है कि घर में बच्चे का जन्म हो या फिर नई दुल्हन आए, घर-मुहल्ले के कुएं की पूजा की जाती है। जिस इलाके में जल की कीमत जान से ज्यादा हो, वहां अपने घर के इस्तेमाल का

यदि बुंदेलखंड के सभी कुओं का अलग से सर्वेक्षण करा कर उन्हें पुनर्जीवित करने की एक योजना शुरू की जाए, तो यह बहुत कम कीमत पर जन भागीदारी के साथ हर घर को पर्याप्त पानी देने का सफल प्रयोग हो सकता है।



पंकज चतुर्वेदी

पानी देने वाले कुएं को मान देना तो बनता ही है। बीते तीन दशकों के दौरान भले ही प्यास बड़ी हो, लेकिन सरकारी व्यवस्था ने घर में तलकूप का ऐसा प्रकोप बरपाया कि कुएं गुम होने लगे। यह सभी जानते हैं कि बुंदेलखंड की जमीन की गहराई में ग्रेनाइट जैसे कठोर चट्टानों का बसेरा है और इसे चीर कर भूजल निकालना लगभग नामुमकिन। असल में यहां स्थापित अधिकांश हैंडपंप बरसात के सीपेज जल पर टिके हैं, जोकि गरमी आते सुखने लगते हैं।

छतरपुर जिला मुख्यालय के पुराना महोबा नाके की छोटी तलेया के आसपास वर्ष 90 तक इस से ज्यादा कुएं होते थे। पुराने नाके के सामने का एक कुआं लगभग दो सौ साल पुराना है। पतली कंक्रीट ईंटों व सूने की लिपाई वाले

इस कुएं के पानी का इस्तेमाल पूरा समाज करता था। विभिन्न मुहल्लों के कुओं में सालभर पानी रहता था और समाज सरकार के भरोसे पानी के लिए नहीं बैठता था। ठीक वही हाल ठीकमगड़, पन्ना और दमोह के थे।

बांदा शहर में तो अब भी 67 कुएं जिंदा हैं। इस शहर के मुहल्लों के नाम कुओं पर ही थे, जैसे- राजा का कुआं, कुन्ना कुआं आदि। 2018 में वहां जिला प्रशासन ने 470 पंचायतों में जनता के सहयोग से कुओं को जिंदा करने का एक कार्यक्रम चलाया था और उसका सकारात्मक असर पिछले साल यहां दिखा भी। वही इलाके के सैकड़ों कुएं ऐसे भी हैं, जहां यदि किसी ने कूद कर आत्महत्या कर ली तो समाज ने उसे मिट्टी से भर कर समाप्त कर दिया। झांसी के खंडेराव गेट के शीतला मंदिर की पंचकुईयां में आज भी सैकड़ों मोटरें पड़ी हैं, जो यहां के कई सौ परिवारों के पानी का साधन हैं। ये कुएं कभी सूखे नहीं।

छतरपुर में ही कोई पांच सौ पुराने कुएं इस अवस्था में हैं कि उन्हें कुछ हजार रुपये खर्च कर जिंदा किया जा सकता है। यदि बुंदेलखंड के सभी कुओं का अलग से सर्वेक्षण करा कर उन्हें पुनर्जीवित करने की एक योजना शुरू की जाए, तो यह बहुत कम कीमत पर जन भागीदारी के साथ हर घर को पर्याप्त पानी देने का सफल प्रयोग हो सकता है।

## वर्षा जल संचयन संयंत्र नहीं लगाने वाले संस्थानों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि राजधानी दिल्ली में वर्षा जल संचयन प्रणाली नहीं लगाने वाले संस्थानों पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) को इसकी कसौटी करने के निर्देश दिए हैं।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने पाया कि कुछ संस्थानों को छोड़कर ज्यादातर स्कूलों एवं कॉलेजों में पर्याप्त मात्रा में वर्षा जल संचय की प्रणाली लगी हुई है। ट्रिब्यूनल को बताया गया कि उसके द्वारा गठित निगरानी समिति ने स्कूलों एवं कॉलेजों में वर्षा जल संचयन लागू करने के बाद दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली विकास प्राधिकरण, पीडब्ल्यूडी, डीएमआरसी के अधीन

इमारतों में इसे लागू करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 31 अक्टूबर 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक डीएमआरसी को कई स्थानों पर वर्षा जल संचयन इकाई लगाने की जरूरत है। डीएमआरसी ने 236 में से 185 जगह पर इसे लगा दिया है जबकि 45 स्थानों पर यह संभव नहीं हो पाया। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

एनजीटी ने जल निकासी के पुनरुद्धार, भूजल के अवैध दोहन और उपचारित पानी का उपयोग करने में विफलता के लिए जुर्माना लगाने के लिए कई दिशा-निर्देश भी दिए। पीठ ने कहा, कि 31 मार्च 2021 तक जल निकासी के पुनरुद्धार में असफल रहने पर प्रति माह 50,000 रुपये का जुर्माना देय होगा। इसे सीपीसीबी द्वारा वसूला जाएगा। एजेंसी

पत्रिका बिग इम्पेक्ट : पत्रिका की जनसरोकार की मुहिम लाई रंग

# बस्तर के 9 गांवों में हैंडपंप से 'जहर' पीने की मजबूरी होगी खत्म

RP-5/2

**बकावंड ब्लॉक के फ्लोराइड प्रभावित 9 गांवों में पाइपलाइन के लिए सर्वे पूरा पीएचई ने तैयार किया 15 करोड़ का प्रोजेक्ट**



पत्रिका ब्यूरो @ जगदलपुर. बस्तर जिले के बकावंड ब्लॉक के 9 फ्लोराइड प्रभावित गांवों की जिंदगी में जल्द बदलाव देखने को मिलेगा। पत्रिका की फ्लोराइड मुक्त बस्तर अभियान के बाद प्रशासन के जिम्मेदारों ने इस दिशा में पहल की है। इसके तहत 9 गांवों में नंदपुरा डेम से पाइपलाइन के जरिए पीने का पानी सप्लाई किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए पीएचई ने सर्वे पूरा कर लिया है। 15 करोड़ रुपए से ज्यादा इस

काम में खर्च होंगे। पत्रिका ने लगातार प्रभावित गांवों से ग्राउंड रिपोर्ट प्रकाशित करके ग्रामीणों के जीवन में घुलते फ्लोराइड के जहर की हकीकत दिखाई।

बस्तर जिले में बकावंड और बस्तर ब्लॉक सबसे ज्यादा फ्लोराइड प्रभावित हैं। बकावंड ब्लॉक के करीब 9 गांवों में फ्लोराइड मानक से

कही ज्यादा है। ऐसे में इन गांवों में 15 करोड़ की लागत से नंदपुरा डेम से पाइप लाइन बिछाकर पेयजल की सप्लाई की जाएगी। इसी प्रकार बस्तर ब्लॉक के फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में कोसारटेडा जलाशय से पानी की सप्लाई की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए सर्वे का काम पूरा हो गया है। इसके लिए डीएमएफ फंड से राशि

'पत्रिका' ने जिन 9 गांवों की समस्या दिखाई वहीं बिछेगी पाइपलाइन बकावंड ब्लॉक के डिमरापाल, बड़े जिराखाल, छोटे जिराखाल, सतोषा, चोखनार, छिंदगांव, बंगला डोंगरी, बागराय और विउरगांव में पाइपलाइन से पेयजल सप्लाई की जाएगी। इसके लिए विउरगांव के पास स्थित नंदपुरा डेम पानी स्टोर किया जाएगा। फिर स्टोर पानी को फिल्टर कर गांवों में सप्लाई की जाएगी। इस के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इंटरकनेक्ट और गांवों में पानी टैंकों का निर्माण किया जाएगा। पत्रिका ने फ्लोराइड मुक्त बस्तर को लेकर जो मुहिम चलाई उसके तहत हमने जिन गांवों की समस्या दिखाई उनमें उक्त गांव भी शामिल हैं। जेबेल डिमरापाल में 22 जनवरी को पत्रिका जनचौपाल का आयोजन भी किया गया था। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी परेशानी बताते हुए निराश्रित पेंशन और मुफ्त इलाज की मांग की थी।

स्वीकृत की जाएगी। इससे जिले के ग्रामीणों को फ्लोराइड से निजात मिल जाएगी।

**बस्तर ब्लॉक के चार गांवों में पाइपलाइन से हो रही सप्लाई :** कोसारटेडा जलाशय से बस्तर ब्लॉक के फ्लोराइड प्रभावित और आयरन प्रभावित चार गांवों में ढाई लाख रुपए की लागत से पाइपलाइन

बिछाकर पेयजल की सप्लाई की जा रही है। वहीं अन्य गांवों में भी इस तरह पानी सप्लाई के लिए प्रपोजल तैयार किया जा रहा है। ताकि लोगों को फ्लोरोसिस के दंश से छूटकारा मिल सके।

**कोसारटेडा से 29 गांव में पहुंच रहा शुद्ध पेयजल :** कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना

के लिए बनाए गए बांध के पानी को पीने योग्य बनाकर करीब 29 गांवों में सप्लाई किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में करीब 49 करोड़ 76 लाख रुपए खर्च किया गया है। इसमें सिर्फ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर करीब 1 करोड़ से अधिक खर्च किया गया है।

बस्तर के फ्लोराइड प्रभावित गांवों में अब पाइप लाइन बिछाकर शुद्ध पेयजल की सप्लाई की जाएगी। फ्लोराइड के स्थायी समाधान के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया था। इसके बाद पीएचई विभाग ने पाइपलाइन से पेयजल पहुंचाने का प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसका सर्वे लगभग पूरा हो गया है।

**लखेश्वर बघेल**

अध्यक्ष, बस्तर विकास प्राधिकरण

# मौसत का सितम: बिलासपुर में सबसे ज्यादा 25 मिमी बारिश, बुधवार को एक-दो स्थानों पर ओले के साथ बारिश की चेतावनी RP 5/2 प्रदेश के तीन संभागों में शीतलहर लौटी, उत्तरी जिलों में झमाझम बारिश

पत्रिका ब्यूरो  
patrika.com

**रायपुर.** पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के तीन संभागों रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा में शीतलहर का आलम रहा। वहीं, बिलासपुर, राजनांदगांव, पेंडारोड में झमाझम बारिश हुई। इससे प्रदेश में दोबारा ठिठुरनभरी ठंड लौट चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को भी प्रदेश के उत्तरी जिलों में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ ओले गिरने के आसार हैं। यह स्थिति आगामी तीन से चार दिनों तक रहने की आशंका है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि हिमालय डिविजन

## कहां कितनी बारिश

|             |      |
|-------------|------|
| बिलासपुर    | 25.0 |
| राजनांदगांव | 15.1 |
| पेंडारोड    | 10.0 |
| अंबिकापुर   | 6.0  |

में पश्चिमी विक्षोभ प्रवेश कर चुका है, जो आगे बढ़ रहा है। इस कारण से खासकर उत्तरी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर और सरगुजा संभाग में शीतलहर की स्थिति है। कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो रही है। दिन के तापमान में सात से आठ डिग्री तक गिरावट आई है। ठंड भी बढ़ गई है।



## तापमान में कितनी गिरावट

|                                            |
|--------------------------------------------|
| रायपुर : 22.6, सामान्य से 7 डिग्री कम      |
| बिलासपुर : 17.4, सामान्य से 11 डिग्री कम   |
| पेंडारोड : 17.6, सामान्य से 8 डिग्री कम    |
| अंबिकापुर : 18.5, सामान्य से 6 डिग्री कम   |
| जगदलपुर : 30.0, सामान्य रहा                |
| दुर्ग : 24.6, सामान्य से 4 डिग्री कम       |
| राजनांदगांव : 22.0, सामान्य से 5 डिग्री कम |

## जाते-जाते फिर बढ़ी ठंड

फरवरी के प्रथम सप्ताह में ठंड लगभग काफूर हो जाती है। यह समय सर्दी की वापसी और गर्मी के मौसम के आमद का समय होता है लेकिन पिछले दो-तीन दिनों से पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव हुआ है। काले बादल छाए हुए हैं। कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो रही है, जिससे सर्दी लौट आई है।